Telangana Today- 26- February-2024

TS declines plea to release water to AP

STATE BUREAU
Hyderabad

Hard-pressed to meet even the drinking water needs under Zone I and Zone II of the Nagarajuna Sagar Project command within Telangana, the State irrigation authorities have declined a request made by the Krishna River Management Board (KRMB) to release about 2 TMC (at the rate of 1,500 cusecs for 15 days) to Andhra ayacut in Zone III of the left canal of the project.

The KRMB wanted the State to release the required quantum of water to AP from March 7. Irrigation officials wrote to KRMB making it clear that even if the water was released from the left canal, the evaporation losses would be more, as it had to flow down from Km 102 to Km 117 of the 21st Main Branch canal and the net realisation at the AP end would be far less than the requirement. Zone III of the NSP left canal serves agricultural lands in Krishna district. Both States had agreed to utilise whatever water was left out in the project only for drinking water purposes till July next. Zone III of the left canal gets water for the irrigated dry crops from November to February in a normal rainfall year.

The Nagarjuna Sagar Left Canal has a total command area of 10.38 lakh acres. Nearly 62 per cent (6.41 lakh acres) of its ayacut falls in Telangana and the rest in AP. Telangana had requested KRMB on February 1 for additional water to meet the drinking water needs up to the end of July 2024. The KRMB, however, wanted the State to stick to its release orders issued on October 9, 2023, permitting the utilisation of only 35 TMC of which it had already utilised 31.17 TMC.

Deccan Chronicle- 26- February-2024

Chief Secretary inspects project sites in city

DC CORRESPONDENT
CHENNAI, FEB. 25

Chief Secretary Shiv Das Meena, Greater Chennai Corporation Commissioner J.Radhakrishnan and other officials during the inspection on Sunday. —DC

Chief Secretary Shiv Das Meena on Sunday carried out inspection at various flood mitigation projects sites in city and suburban areas.

CS visited the sites at Adyar River banks in ward 157 in Alandur zone where river bank strengthening work from MIOT Junction to airport is in progress with ₹24.80 cr. Later he took stock of canal construction works in Manapakkam Road to carry water from Porur lake.

Protection wall construction works and cleaning up works at Kolapakkam Road worth ₹8.74 cr is also underway. CS made a visit to that site as well. He also inspected ₹9.7 cr culvert works in Maduravoyal Bypass Road, ₹4crworks at Velachery Main Road , River Restoration works at Teynampet worth ₹42.5 cr,.

Speaking to reporters, CS said that various flood mitigation works in the area like Kolapakkamm, Mugalivakkam and Manapakkam with Rs 180 Cr. Once the works are completed, the water from Porur Lake can easily reach the Adyar River. Various works under the Highways department are going to various parts of the city including Velachery-Tambaram Highway. The officials are asked to expedite the works and complete the project in a time-bound manner, he said.

Sandeep Saxena, Additional Chief Secretary, Water Resource department, J. Radhakrishnan, Commissioner , Greater Chennai corporation and other officials accompanied the Chief Secretary.

Millennium Post- 26- February-2024

'Yamuna Jan Jagran Abhiyan' continues to witness success

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The 'Yamuna Jan Jagran Abhiyan', under the Yamuna Action Plan-II led by the Delhi Jal Board, continues to witness success as Delhiites enthusiastically participate in the campaign to clean the Yamuna river.

Jointly spearheaded by the Delhi Jal Board and Partner NGOs as part of Yamuna Action Plan-III, the campaign has garnered massive support from the citizens of Delhi, with over 248,000 individuals actively engaged in the movement to preserve the river.

Through a myriad of activities including street plays, door-to-door awareness campaigns, focused group discussions, and workshops, the campaign aims to educate and mobilise communities towards the conservation of the Yamuna.

Last month alone, the campaign witnessed the participation of 12,260 individuals, indicating a surge in its popularity and effectiveness. Partner NGOs such as Ganga Devi Educational Society, Hariyali Center for Rural Development, Rural Education and Welfare Society, and Social Network India are playing a pivotal role in implementing the Jan Jagran Abhiyan across different areas of Delhi, fostering direct engagement with local communities.

Moreover, efforts are underway to empower communities residing along the banks of the Yamuna by providing them with training and skill-building opportunities, thereby strengthening their livelihoods.

Under Yamuna Action Plan-III, targeted districts including East, North-East, West, North-West, South, and South-West Delhi are being prioritised for the expansion of sewerage networks and the implementation of awareness campaigns. Special emphasis is placed on engaging unauthorised colonies and villages where sewerage facilities are lacking.

Vishwas Express- 26- February-2024

ईआरसीपी से 13 जिलों को मिलेगी 50 साल तक पानी की गारंटी: शेखावत

केंद्रीय मंत्री ने आभार यात्रा के दूसरे दिन धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक और जयपुर जिलों में सभाएं की

विश्वास एक्सप्रेस

जयपुर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) आभार यात्रा के दूसरे दिन रविवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक और जयपुर जिलों में सभाएं की। सभाओं में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि ईआरसीपी से आगामी 40-50 साल तक पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनता को पानी की गारंटी मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि कभी यहां प्रचुरता में जमीन में पानी उपलब्ध रहता था, लेकिन अब वो रसातल में चला गया है। पानी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। अटल जी की सरकार नदी जोड़ो परियोजना लेकर आई थी, जिसमें पार्वती-कालीसिंध-चंबल भी एक लिंक था, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सहमति नहीं बनी। वर्ष 2004 में अटल जी की सरकार दोबारा नहीं बन पाई और कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने इसे 10 साल लटका दिया। वर्ष 2016 में वसुंधरा जी ने इससे हटकर ईआरसीपी की परिकल्पना की, लेकिन वर्ष 2018 में दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई।

शेखावत ने कहा कि वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। गहलोत साहब को हमने लिखा कि आप मध्य प्रदेश से समझौता कर लीजिए, हम आपको ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन जनवरी 2019 में गहलोत साहब को चिट्ठी लिखकर मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया कि यह मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। हम कोई समझौता नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि तब से गहलोत ईआरसीपी को राजनीतिक भस्मासुर की तरह खड़ा कर रहे थे। मुझे और प्रधानमंत्री जी को कठघरे में खड़ा कर रहे थे। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया और उनसे निवेदन किया कि तकनीकी कमी राजस्थान पूरा करता नहीं है। हमको अपराधी बनाने के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ नया सोचो और आगे बढ़ो। तब हमने पीकेसी-ईआरसीपी को कैसे जोड़ सकते हैं, इसको लेकर देश भर के पानी को समझने वाले इंजीनियर को बुलाया। तब यह नया रास्ता निकाला।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले मैंने अलवर से लेकर जयपुर समेत सभी 13 जिलों की यात्रा की थी। मैंने बताया था कि कैसे राजस्थान की गहलोत सरकार ईआरसीपी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कैसे साढ़े तीन करोड़ लोगों के सुख कंठों और लाखों किसान के साथ राजनीति की जा रही है। लोकतंत्र में लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किसी पाप से काम नहीं

हो सकता। तब मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनने दीजिए, अगले 1 महीने में मध्य प्रदेश से समझौता कर आपके सपनों की जीवन रेखा को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी से आगामी 40-50 साल तक जनता को पानी की गारंटी मिलेगी। शेखावत ने त्वरित गति से कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी जताया।

गहलोत ने योजनाएं लटकाई और अटकाई

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में देश में मात्र 16 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचता था। ग्रामीण क्षेत्रों में देश में 19 करोड़ 40 लाख परिवार रहते हैं। मेरी माता-बहनों को 5-10 किलोमीटर रोजाना पानी के लिए चलना पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने इससे उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। कोरोना की आपदा और जल राज्यों का विषय होने के बावजूद देश में 10 प्रांतों में 100 प्रतिशत घरों तक पीने का पानी पहुंच गया है। आज 75 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है। राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए यहां सबसे ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराए, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के लिए गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना या उसके लिए योजना बनाना प्राथमिकता नहीं थी। उनके लिए प्राथमिकता थी कि वोटबैंक किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। अशोक गहलोत ने केवल योजनाओं का लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम किया। राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उन्होंने मात्र 6000 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें भी भ्रष्टाचार का तूफान खड़ा करने का काम किया। प्रदेश की जनता ने उनको सजा दी और सत्ता की कुर्सी से खींचकर नीचे पटक दिया।

गरीबों का जीवन बदला

शेखावत ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल धरातल पर अपनी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकला है। गरीब को घर, शौचालय, गैस, बैंक खाता, गांव तक सड़क, सस्ता इंटरनेट, स्वास्थ्य के खर्च की चिंता से मुक्ति देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि अबकी बार 400 के पार जाएंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सुबह धौलपुर के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर दर्शन-पूजन पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ता के साथ सुना। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने को लेकर कहीं जरा भी संदेह किसी के मन में नहीं है। सभी पूर्णत: आश्वस्त हैं।

Rajasthan Patrika- 26- February-2024

माय सिटी माय प्राइड : साबरमती नदी की सफाई में बंटाया हाथ

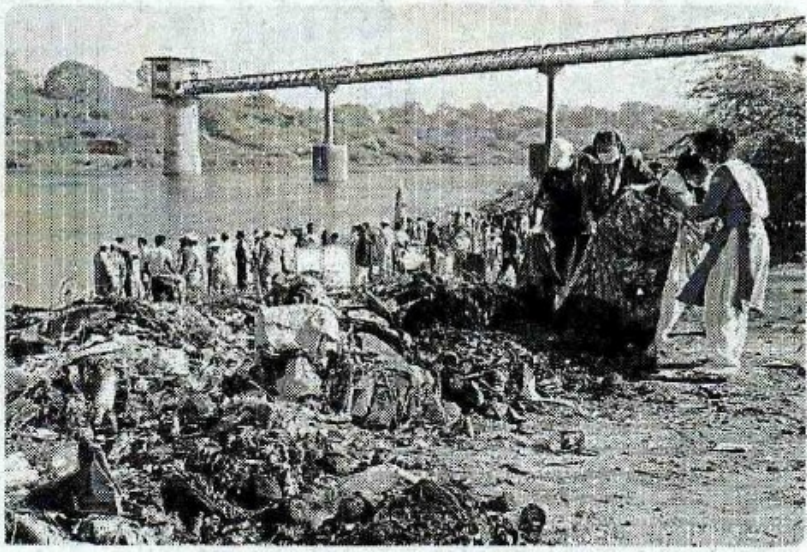

अहमदाबाद @ पत्रिका. महानगरपालिका के उत्तरजोन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग, साबरमती रिवरफ्रंट के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा संत निरंकारी चेरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों ने रविवार को इंदिरा ब्रिज के नीचे छठ घाट के आसपास साबरमती नदी की सफाई की। लगभग 750 लोगों ने माय सिटी माय प्राइड, स्थानीय लोगों को जागरूक करने तथा जल स्रोतों के संरक्षण के तहत नदी में मिले कूड़े को निकाला। नदी से लगभग आठ टन कूड़ा निकाला गया, जिसे डंप साइट पहुंचाया गया। सफाई का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।